

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2012(1)

986

के. कन्नन से पहले, जे.

सूड ब्रदर्स, -याचिकाकर्ता बनाम

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ और अन्य, उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5886-2009

26 सितंबर, 2011

भारत का संविधान-अनुच्छेद 14 और 226-पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम 1961-एस। 9, 10, 13-नीलामी प्लेटफॉर्म नियम 1981-आर. एल. का लाइसेंस। 4, 20 और 21-सामान्य खंड अधिनियम-एस। 26-लाइसेंस का नवीनीकरण-अधिकार का मामला-नीलामी मंच के आवंटन का अधिकार, यदि यह पहले से मौजूद है, तो सह-अस्तित्व में है-व्यवसाय के स्थान के परिवर्तन को अस्वीकृति का आधार नहीं बनाया जा सकता है-मंडी बोर्ड हालांकि अस्तित्व में व्यवसाय के स्थान पर परिवर्तन को अस्वीकार करने के लिए सक्षम है।

माना जाता है कि लाइसेंस के रूप में व्यवसाय का स्थान शामिल है। लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन पत्र में लाइसेंस के प्रपत्र का विवरण भी भरना आवश्यक है। अधिनियम की खंड 10 के तहत लाइसेंस जारी किया जाता है। खंड 10 या 13 के तहत प्राप्त लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति देने वाले प्रासंगिक नियम 21 में लाइसेंसधारक को केवल अधिसूचित क्षेत्र के भीतर व्यवसाय के स्थान के परिवर्तन के संदर्भ में इस तरह के नवीनीकरण प्राप्त करने के लिए कोई बाधा नहीं है। वास्तव में लाइसेंस जारी करने के अधिकार के साथ सामान्य खंड अधिनियम की खंड 26 के तहत संशोधन या सुधार करने का अधिकार है। याचिकाकर्ता को लाइसेंस के नवीनीकरण के अधिकार से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवेदन के रूप में, एक लाइसेंसधारी ने अधिसूचित क्षेत्र के भीतर व्यवसाय का स्थान बदल दिया है।

(पैरा 5)

एक मात्र लाइसेंसधारी, जिसके पास दुकान नहीं है, को नीलामी मंच का अधिकार नहीं हो सकता है। चूंकि विवाद वरिष्ठता खोने की संभावना और नीलामी मंच में स्थान की पात्रता के नुकसान के इर्द-गिर्द केंद्रित है, इसलिए मेरा मानना है कि एक लाइसेंसधारी को नीलामी मंच का अधिकार नहीं हो सकता है यदि वह कुछ क्षमता में किसी दुकान का अधिकार नहीं रखता है।

सूद बरदर्स बनाम यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़

और अन्य (के. कन्नन, जे.)

मालिक या किरायेदार के रूप में। हालाँकि, इस मामले में ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ता की परिसर के भीतर कोई दुकान नहीं है। उन्होंने दुकान का पट्टा No.12 लिया है और नवीनीकरण का दावा केवल दुकान No.12 पर उनके व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। इसलिए, उसे लाइसेंस के नवीनीकरण के अधिकार या नीलामी मंच में स्थान के आवंटन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, अगर उसके पास पहले से ही ऐसा अधिकार है।

(पैरा 9)

विकास बहल, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता (2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.5886 में) और प्रतिवादी संख्या 5 (2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.12684 में)

चेतन मित्तल, कुणाल मुलवानी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता (2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.12684 में) और प्रतिवादी संख्या 5 (2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.5886 में)

परवीन गौर, प्रतिवादी नंबर 1 जे. आर. सयाल के लिए अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए नंबर 2 से 4 के लिए अधिवक्ता

के. कन्नन, जे.

I. लिस का विषय: बाजार में व्यवसाय के नए स्थान के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना।

(1) याचिकाकर्ता ने पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाता है) के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए अपने आवेदन को कच आरती के रूप में अस्वीकार करने को चुनौती दी है। स्वीकार किया गया मामला यह है कि वह वर्ष 1970 से लाइसेंसधारी था और वह एससीएफ 27, सब्जी मंडी, सेक्टर-26, चंडीगढ़ से अपना व्यवसाय चला रहा था। याचिकाकर्ता को मकान मालिक द्वारा बेदखल कर दिया गया था और उसने उसी मंडी में एससीएफ 12 के एक अन्य मालिक के साथ एक नया समझौता किया था। आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि नवीनीकरण एससीएफ 27 में उसी दुकान के संबंध में नहीं था, बल्कि यह दुकान

एससीएफ 12 के लिए था और जब उसने दुकान को दूसरे परिसर में बदल दिया है तो नियम नवीनीकरण की अनुमति नहीं देता है।

II. लाइसेंस का नवीनीकरण एक अधिकार है; नियम 20 के तहत व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है; नियम 21 के तहत व्यवसाय के विभिन्न स्थानों के लिए नवीनीकरण हालांकि वर्जित नहीं है।

(2) याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अधिनियम की योजना और नियम 21 के तहत प्रासंगिक नियम नवीकरण के अधिकार का प्रावधान करते हैं और राहत को केवल इस आधार पर अस्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि उस परिसर में बदलाव किया गया था

2012(1)

988

व्यवसाय पहले ही स्थापित हो चुका था। विद्वान अधिवक्ता खंड 10 में उस भाषा को संदर्भित करता है जो लाइसेंसधारियों के लिए आवेदन प्रदान करती है, जो "किसी भी व्यक्ति" को लाइसेंस के लिए खंड 9 के तहत निर्दिष्ट प्राधिकरण को आवेदन करने में सक्षम बनाती है। वकील नियम 20 का उल्लेख करेगा, जो एक लाइसेंसधारी को उस व्यवसाय के विवरण में अंकन जोड़ या हटाने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है जिसके लिए उसे लाइसेंस जारी किया गया है। उनके अनुसार इसमें परिसर में बदलाव भी शामिल होगा।

(3) याचिकाकर्ता के वकील, एस। विकास बहल कुछ उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं जहां इस तरह के बदलाव किए गए हैं और मेरे सामने आर. टी. आई. अधिनियम के तहत दायर आवेदनों द्वारा से एकत्र किए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से पेश वकील ऐसे उदाहरणों को स्वीकार करता है, लेकिन वह तर्क देगा कि ये स्पष्ट रूप से अनियमितताएं थीं और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो अधिनियम के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदनों में व्यवसाय के स्थान पर परिवर्तन का मनोरंजन करने के लिए जिम्मेदार थे। मैं इसे वहीं रहने दूंगा और याचिकाकर्ता को पते में बदलाव की मांग करने का अधिकार देने के लिए पक्षों के अधिकारों को नियंत्रित करने के रूप में प्रभावित ऐसे परिवर्तनों के उदाहरणों का हवाला नहीं दूंगा, क्योंकि उत्तरदाता संख्या 2 और 3 स्वीकार करते हैं कि उनके शुरुआती कार्य गलत थे।

(4) इस तर्क का जवाब देते हुए कि नियम 20 के तहत आवेदन पर विचार किया जा सकता है, बाजार समिति की ओर से पेश वकील का तर्क है कि लाइसेंस का रूप स्वयं दो विवरणों के लिए स्पष्ट रूप से प्रदान करता है, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यवसाय का विवरण जिसके लिए लाइसेंस कॉलम संख्या अन्य बातों के साथ साथ मान्य है। 5 और कॉलम नं. में व्यवसाय का स्थान। 6. इसलिए, वकील उस फर्म की शैली और सदस्यता में परिवर्तन का विरोध करेगा जिस पर नियम 20 विचार करता है और व्यवसाय के विवरणों में जोड़ या हटाने की अंकन जिसके लिए उसे लाइसेंस जारी किया गया है, कॉलम संख्या में निर्दिष्ट विवरणों में किसी भी परिवर्तन के रूप में समझा जाना चाहिए। 5. नतीजतन, व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन, जो एक अलग खंड है, को खंड

20 के तहत परिवर्तन के लिए याचिका में समायोजित नहीं किया जा सकता है। मैं इस तर्क को बरकरार रखता हूँ और मानता हूँ कि मंडी बोर्ड यह कहने में सक्षम होगा कि धारा 10 या 13 के तहत जारी मौजूदा लाइसेंस में व्यवसाय के स्थान में बदलाव करना संभव नहीं है।

(5) हालाँकि, मैं लाइसेंस के नवीनीकरण के अधिकार से इनकार नहीं करता, भले ही लाइसेंसधारी को बाजार क्षेत्र के भीतर व्यवसाय का स्थान बदलना पड़े। अनुज्ञप्ति के रूप में व्यवसाय का स्थान शामिल होता है।

सूद बरदर्स बनाम यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़

और अन्य (के. कन्नन, जे.)

आवेदन पत्र लाइसेंस जारी करने के लिए भी लाइसेंस के प्रपत्र के विवरण भरने की आवश्यकता होती है। अधिनियम की खंड 10 के तहत लाइसेंस जारी किया जाता है। खंड 10 या 13 के तहत प्राप्त लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति देने वाले प्रासंगिक नियम 21 में लाइसेंसधारक को केवल अधिसूचित क्षेत्र के भीतर व्यवसाय के स्थान के परिवर्तन के संदर्भ में इस तरह के नवीनीकरण प्राप्त करने के लिए कोई बाधा नहीं है। वास्तव में लाइसेंस जारी करने के अधिकार के साथ सामान्य खंड अधिनियम की खंड 26 के तहत संशोधन या सुधार करने का अधिकार है। याचिकाकर्ता को लाइसेंस के नवीनीकरण के अधिकार से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवेदन के रूप में, एक लाइसेंसधारी ने अधिसूचित क्षेत्र के भीतर व्यवसाय का स्थान बदल दिया है। यह वास्तव में याचिकाकर्ता के दावे को बरकरार रखते हुए रिट याचिका का निपटारा करना चाहिए, लेकिन नीलामी मंच में आवंटन से संबंधित एक सहायक मुद्दा विवाद का वास्तविक विषय बन जाता है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता नवीनीकरण के दावे की अस्वीकृति से व्यथित महसूस करता है और केवल एक नया आवेदन करने में संकोच करता है क्योंकि ऐसी प्रक्रिया से वह नीलामी मंच पर अपने दावे को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा।

III. लाइसेंस के नवीनीकरण के साथ नीलामी मंचों के अधिकार के आवंटन का अधिकार होता है, यदि यह पहले से मौजूद है।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह इंगित करेंगे कि यदि लाइसेंस को सरेंडर कर दिया जाना चाहिए और एक नया लाइसेंस प्राप्त किया जाना है, तो वह वरिष्ठता खो देगा और जैसा कि बाजार समिति के लिए होता है, वे नए लाइसेंसधारी से एक शपथ पत्र सुरक्षित करेंगे कि वह नीलामी मंच के लिए कोई दावा नहीं करेगा। एक पुराने लाइसेंसधारी के रूप में याचिकाकर्ता, जिसके पास उस समय के दौरान एक नीलामी मंच है जब वह एससीएफ 27 में एक दुकान चला रहा था, अगर एक नया आवेदन दायर किया जाना था, तो नीलामी मंच खोने की संभावना का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि, वह यह इंगित करेंगे कि उनके मकान मालिक, जो 5 वें प्रतिवादी हैं, को स्वयं इस तथ्य से कोई कठिनाई नहीं हुई कि अधिकारियों ने 5 वें प्रतिवादी के साथ हाथ मिलाया और उन्हें नीलामी मंच में जगह आवंटित करने के लिए एक अलग पैमाना लागू किया, भले ही

जिन व्यक्तियों को 5 वें प्रतिवादी से पहले लाइसेंस दिए गए थे, उन्हें शपथ पत्र देने के लिए मजबूर किया गया था कि वे नीलामी मंचों में किसी भी आवंटन की मांग नहीं करेंगे।

(7) वरिष्ठ अधिवक्ता श्री. पांचवें प्रतिवादी की ओर से पेश चेतन मित्तल ने इस बात से इनकार किया और वह तर्क देंगे कि प्रत्येक दुकान एक विशेष नीलामी मंच से जुड़ी है और यदि याचिकाकर्ता को एससीएफ 27 से बेदखल कर दिया गया था, तो नीलामी मंच केवल आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के हिस्से के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

2012(1)

990

एस. सी. एफ. 12 के लिए चिह्नित। वकील मुझे कुछ उदाहरण भी दिखाएंगे कि कैसे जब व्यक्तियों द्वारा नए लाइसेंस दिए गए थे, जिनकी अन्य दुकानें थीं, तो उन्हें संबंधित दुकानों से जुड़े नीलामी मंचों में भी स्थान आवंटित किए गए थे। उदाहरण के लिए, क्र. सं. 8 में मेसर्स बंशतु एप्पेल कंपनी को 16.08.2004 पर लाइसेंस दिए जाने की सूचना मिली थी और उन्हें SCF 23 से जुड़ा नीलामी मंच दिया गया था। वह कई अन्य लाइसेंसधारियों का भी हवाला देंगे, जिन्हें नए लाइसेंस देने पर विशिष्ट एससीएफ के खिलाफ नीलामी मंच आवंटित किए गए थे।

(8) चूंकि याचिकाकर्ता की शिकायत केवल यह थी कि यदि वह अपना लाइसेंस सौंप देता है और नए लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, तो वह वरिष्ठता खो सकता है और वह नीलामी मंच में किसी भी आवंटन के लिए दावा छोड़ने के लिए मजबूर हो सकता है, इसलिए मैंने बाजार समिति की ओर से पेश वकील से पूछा कि क्या याचिकाकर्ता इतनी वरिष्ठता खो देगा और क्या वह उसी तरह से एक शपथ पत्र देने के लिए मजबूर होगा जैसे कुछ नए लाइसेंसधारियों को नीलामी मंचों के आवंटन के लिए अपर्याप्त स्थान देने के लिए मजबूर किया गया है। समिति के वकील इस बात का कोई आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं थे कि नीलामी मंच में याचिकाकर्ता को वरिष्ठता के आधार पर कोई स्थान दिया जाएगा।

(9) इसलिए सवाल यह होगा कि क्या किसी प्लेटफॉर्म में किसी विशेष क्षेत्र का अनुमान लगाना और उसे दुकान से जोड़ना संभव है, जो विशेष रूप से मालिक के रूप में या पट्टेदार के रूप में सुरक्षित है। यद्यपि याचिकाकर्ता के वकील ने इस तर्क के साथ शुरुआत की कि किसी भी व्यक्ति के लिए अनुज्ञापतिधारी होना संभव है, भले ही बाजार समिति के भीतर उसकी कोई दुकान न हो, चौथे प्रतिवादी के वकील ने इंगित किया

और मेरे विचार में नीलामी मंच नियम 1981 के अनुज्ञप्ति के लिए जो पात्रता की शर्तों को स्पष्ट करता है और खंड 4 (बी) निम्नानुसार प्रदान करता है:

“4. पात्रता की शर्तें-जब तक कि बाजार समिति

अन्यथा निर्णय लें, निम्नलिखित नीलामी मंच और उस पर एक लाइसेंस के अनुदान के लिए पात्र होंगे:

(a) x x x x x x x x

(ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति धारक जो वास्तव में सेक्टर 26, चंडीगढ़ के बाजार क्षेत्र में फलों और सब्जियों के व्यापार के लिए संपदा अधिकारी, चंडीगढ़ द्वारा आवंटित किसी भी दुकान/स्थल पर फलों और सब्जियों का व्यापार करता है।”

991

सूद ब्रदर्स बनाम यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़

और अन्य (के. कन्नन, जे.)

इसलिए मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि लाइसेंस देने के लिए खंड 10 के तहत "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति को उपरोक्त नियम के संदर्भ के बिना नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि नीलामी मंच के लिए दावा किया जाता है। एक मात्र लाइसेंसधारी, जिसके पास दुकान नहीं है, उसे नीलामी मंच का अधिकार नहीं हो सकता है। चूंकि विवाद वरिष्ठता खोने की संभावना और नीलामी मंच में स्थान की पात्रता के नुकसान के इर्द-गिर्द केंद्रित है, इसलिए मेरा मानना है कि एक लाइसेंसधारी को नीलामी मंच का अधिकार नहीं हो सकता है यदि वह मालिक या किरायेदार के रूप में किसी क्षमता में दुकान का अधिकार नहीं रखता है। हालाँकि, इस मामले में ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ता की परिसर के भीतर कोई दुकान नहीं है। उन्होंने दुकान का पट्टा No.12 लिया है और नवीनीकरण का दावा केवल दुकान No.12 पर उनके व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। इसलिए, उसे लाइसेंस के नवीनीकरण के अधिकार या नीलामी मंच में स्थान के आवंटन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, अगर उसके पास पहले से ही ऐसा अधिकार है।

(10) यदि नवीनीकरण के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता से इनकार नहीं किया जा सकता है और नियमों के अनुसार नीलामी मंचों में स्थान के आवंटन के लिए भी योग्य माना जाता है, तो मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता नीलामी मंच में अपने दावे को जब्त किए बिना नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। मैंने अधिनियम और नियमों के

प्रावधानों को देखा है और वे कहीं भी यह नहीं कहते हैं कि प्रत्येक दुकान का नीलामी मंच में एक विशिष्ट स्थान के द्वारा एक स्थान होगा। नियमों की आवश्यकताओं में परिसर में दुकान रखने की आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं बताया गया है। नीलामी मंच में इसकी क्या जगह होगी, यह अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान द्वारा से निर्धारित नहीं किया गया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नीलामी मंचों में जगह की कमी है और इसलिए, उन व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए एक व्यावहारिक नीति होनी चाहिए, जो लाइसेंसधारी हैं। यह तथ्य की बात है कि नीलामी मंचों में जगह की उपलब्धता के संदर्भ के बिना कई व्यक्तियों को लाइसेंस दिए गए हैं। इसलिए, नए लाइसेंसों के अनुदान में एक प्रतिबंध होना चाहिए, जो नवीनीकरण की प्रकृति में नहीं हैं ताकि नीलामी मंचों में जगह की उपलब्धता कोई मुद्दा न हो। यदि इस तरह का प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, तो इस मुद्दे को न्यायोचित रूप से संबोधित करने का एकमात्र तरीका 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर वरिष्ठता के आधार पर नीलामी मंच पर अधिकार संलग्न करना होगा। यह शायद सबसे आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन यह नीलामी मंचों में जगह की अनुपलब्धता की वास्तविकता के लिए कम से कम आवश्यक है। 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार का यह तर्क देकर उल्लंघन नहीं किया जा सकता है कि वह नीलामी मंच, आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा का अधिकार खो देगा।

2012(1)

992

जिस क्षण कोई लाइसेंसधारी किसी विशेष दुकान पर नियंत्रण खो देता है और उसे बाजार क्षेत्र के भीतर किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे कि जब वह किरायेदार के रूप में दुकान पर होता है और उसे उसके मकान मालिक द्वारा बेदखल कर दिया जाता है। इस मामले में, जो विशिष्ट स्थिति सामने आई है, वह यह है कि याचिकाकर्ता, जो एक किरायेदार था, को मकान मालिक द्वारा बेदखल कर दिया जाता है और मकान मालिक, जो बाद में आता है, किरायेदार को यह निर्देश देना चाहता है कि भले ही वह परिसर में एक नई दुकान प्राप्त करे, याचिकाकर्ता जैसे पहले का लाइसेंसधारी नीलामी प्लेटफार्मों को बनाए रखने के लिए दावा नहीं कर सकता है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है, तो किरायेदार, जो एक लाइसेंसधारी है, और जिसके पास नीलामी मंच है, नीलामी मंच खो सकता है। यह एक हास्यास्पद तर्क स्थिति की ओर भी ले जाएगा जब किसी भी कारण से मकान मालिक मंडी के भीतर एक किरायेदार को बाहर निकाल देता है और खुद कच आरती के रूप में लाइसेंस नहीं लेना चाहता है। यदि मंडी में किसी स्थान को विशेष रूप से किसी विशेष दुकान से जोड़ा जाना है, तो दुकान का

मालिक, जो लाइसेंसधारी नहीं है, नीलामी मंच में एक स्थान को उपयोग में लाए बिना बंद कर देगा और किसी अन्य लाइसेंसधारी के लिए भी उस स्थान का उपयोग करना संभव नहीं बनाएगा। यह सरासर असमान होगा।

(11) ऐसा लगता है कि हाल ही में अधिकारियों द्वारा प्रत्येक दुकान को नीलामी मंच में एक स्थान से जोड़ने का प्रयास किया गया है। जब तक अधिनियम में कोई नियम या प्रावधान नहीं हैं, ऐसा कोई भी प्रयास, जो मौजूदा लाइसेंस धारकों को प्रभावित करेगा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि

"चिंतराम कौर बनाम पंजाब राज्य" (1) में कि एक लाइसेंस दिया गया है

अधिनियम और नियमों के तहत लाइसेंसधारी को बाजार समिति के क्षेत्र के भीतर कहीं भी अपना व्यवसाय चलाने का अधिकार है। ऐसा हो सकता है कि एक नया लाइसेंसधारी नीलामी मंच के रूप में अपनी दुकान का उपयोग ऐसी स्थिति में कर सकता है जहां कोई नीलामी मंच उपलब्ध न हो। हालाँकि, नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले मौजूदा लाइसेंसधारक को अपना नीलामी मंच खोने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है, अगर उसके पास पहले से ही एक था।

(12) 5 वें प्रतिवादी ने 2009 का सी. डब्ल्यू. पी. No.12684 दायर किया है, जिसमें याचिकाकर्ता को 2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.5886 में दुकान No.27 के खिलाफ नीलामी मंच के आवंटन को चुनौती दी गई है, क्योंकि वह खाली हो गया है और दुकान No.12 में स्थानांतरित हो गया है। मेरे इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि नीलामी मंच के अधिकार को किसी विशेष दुकान संख्या से जोड़ा नहीं जा सकता है, इस रिट याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। 2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.5886 में रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ मांगे गए प्रतिबंध को भी तब तक नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि याचिकाकर्ता को नीलामी मंच में पर्याप्त वैकल्पिक स्थान का बाजार समिति द्वारा आश्वासन नहीं दिया जा सकता है, जो उसकी वरिष्ठता और उसके द्वारा अर्जित अधिकार के अनुरूप है।

(1) 1996(1) आरआरआर 626 993

एम. एच. डी. नजीर और अन्य बनाम पंजाब राज्य

और अन्य (एम. एम. कुमार, जे.)

वी. स्वभाव

(13) इसलिए व्यवस्था यह है कि 2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.5886 में याचिकाकर्ता को उसके लाइसेंस के नवीनीकरण के अधिकार के रूप में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और नियम 21 के तहत नवीनीकरण के लिए उसका आवेदन, किसी भी प्रकार के शपथ पत्र पर जोर दिए बिना दुकान एस. सी. एफ. 12 के लिए दिया जाएगा कि नीलामी मंच में उसकी कोई जगह नहीं होगी। याचिकाकर्ता को उस स्थान को बनाए रखने का अधिकार है जो उसके पास है, जब तक कि कोई अन्य वैकल्पिक नीति अधिनियम या नियमों में संशोधन द्वारा से नहीं आती है, जो मौजूदा अधिकारों पर विधिवत ध्यान देगी जो उचित और न्यायसंगत हैं।

(14) रिट याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के साथ किया जाता है।

एस. गुप्ता

**एम. एम. कुमार, ए. सी. जे. और गुरदेव सिंह, जे. एम. एच. डी. से पहले।
नजीर और अन्य-याचिकाकर्ता**

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य,-उत्तरदाता 1991 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16745

13 सितंबर, 2011

भारत का संविधान-अनुच्छेद 1-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-एस. एस. 4, 6, 11, 11-पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट, 1922-धारा 42 (2)-इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा बनाई गई विकास योजना-भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा पारित पुरस्कार-याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके पक्के निर्माण वाले आवासीय घर अधिग्रहित भूमि के एक हिस्से पर मौजूद थे, लेकिन कलेक्टर ने पुरस्कार की घोषणा करते समय सुपर-स्ट्रक्चर के लिए राशि निर्धारित नहीं की है-कलेक्टर द्वारा पारित सुपर-स्ट्रक्चर के संबंध में पूरक पुरस्कार-पुरस्कारों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे अधिकार क्षेत्र के बिना थे और घोषणा की तारीख से दो साल की वैधानिक अवधि के बाद पारित किए गए थे-माना:

(i) यह पुरस्कार सुपर-स्ट्रक्चर के संबंध में निर्णय को पीछे रखते हुए भूमि के संबंध में दिया जा सकता है जिसका मूल्यांकन बाद में किया जा सकता है।

((ii) अनुपूरक पुरस्कार बाद में भूमि पर सुपर-संरचनाओं का मूल्यांकन करते हुए दिया जा सकता है।

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता । सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

gurvinder kaur